



2026:AHC:66918-DB

25.03.2026 को सुरक्षित

31.03.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या- 324 वर्ष 2026

प्रेम सागर अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 3

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी द्वारा)

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री अशोक खरे और राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता की सहायता से सुनवाई की। यासीन, अपीलकर्ता के अधिवक्ता और श्री राजीव गुप्ता, राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान विशेष अपील रिट ए संख्या-18316 वर्ष 2025 (प्रेम सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 10.02.2026 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने आक्षेपित आदेश में दर्ज निष्कर्षों से व्यथित महसूस करते हुए, इस अंतर-न्यायालय अपील में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रस्तुत अपील की उत्पत्ति अपीलकर्ता के सेवा इतिहास में निहित है, जिसे शुरू में क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, असफपुर, बदायूं में मैकेनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता की नियुक्ति तीन महीने की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी प्रकृति की थी, लेकिन दिनांक 02.02.1993 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ता की नियुक्ति को तदर्थ आधार पर 31.03.1993 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता को एक और विस्तार दिया गया, जो 21.04.1993 तक जारी रहा। अपीलकर्ता का कार्यकाल किसी और विस्तार के अभाव में स्वचालित रूप से समाप्त हो गया, जिससे उसे अपनी सेवाओं की समाप्ति को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-27234 वर्ष 1993 दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 11.08.1993 को, उपर्युक्त रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को कानून के अनुसार उसी पद के खिलाफ चयन सहित प्रतिपक्षियों को नियमित चयन करने की स्वतंत्रता देते हुए एक मैकेनिक के रूप में जारी रखने में सक्षम बनाया गया था। दिनांक 11.08.1993 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता 16.08.1993 को अपने कर्तव्यों में फिर से शामिल हो गया और अपने कार्यों का निर्वहन जारी रखा। इसके अलावा, उन्हें समय-समय पर वेतन वृद्धि, वेतन आयोगों के तहत लाभ, सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) अनुदान और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाता खोलने से भी लाभ हुआ।

4. यह तथ्य की बात है कि रिट याचिका संख्या-27234 वर्ष 1993 जिसके तहत अपीलकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, को इस न्यायालय ने दिनांक 02.04.2012 के अपने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। रिट याचिका को खारिज करते हुए, इस अदालत ने माना कि अपीलकर्ता की प्रारंभिक सगाई एक स्टॉपगैप व्यवस्था की प्रकृति में थी, जो खुले चयन की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना या बड़े पैमाने पर जनता से आवेदन आमंत्रित करके की गई थी, और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता को इस तरह की स्टॉपगैप व्यवस्था के आधार पर 21.04.1993 के बाद सेवा में निरंतरता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस कारण से, याचिका खारिज कर दी गई थी।



5. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि रिट याचिका खारिज होने के बाद भी, अपीलकर्ता ने बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। इसके बाद, 01.08.2023 को, अपीलकर्ता ने 2021 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों (लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के पदों पर) नियमितीकरण, 1979 के प्रावधानों के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दायर किया। प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, असफपुर, बदायूं को संबोधित अभ्यावेदन में, उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्होंने पहले ही 23.03.2022 को नियमितीकरण का अनुरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है, और उसके संदर्भ में, उन्होंने यह कहते हुए अपना अनुरोध दोहराया कि 16.08.1993 से, वह लगातार 975-25-1150-3-1660 के ग्रेड वेतन पर 'मैकेनिक' के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें वेतनवृद्धि, 6 वें वेतन आयोग और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) कटौती का लाभ मिल रहा था, और चूंकि उनकी सेवा के केवल तीन साल बचे हैं, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि गैर-नियमितीकरण उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को प्रभावित करेगा, इसलिए, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आदेश 11/2021/13/30/2021 Ka-1-2021 दिनांक 16.12.2021 के अनुसार, जो प्रदान करता है कि तीन साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी रिक्त पदों पर नियमित होने के पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उन्होंने 30 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, इसलिए उन्हें नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत नियमित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

6. अपने अभ्यावेदन को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानाचार्य ने अपना सिफारिश पत्र दिनांक 14.10.2023 को महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, बखशी तालाब, लखनऊ के माध्यम से अग्रेषित किया। अपने अनुशंसा पत्र में उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने निरंतर सेवा के 30 साल संतोषजनक ढंग से पूरे कर लिए हैं। पत्र में, यह भी कहा गया था कि उन्हें नियमित वेतन, वेतन वृद्धि और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) लाभ आदि मिल रहे थे, हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि 21.04.1993 के बाद, कार्यालय के पास उनकी सेवा के विस्तार के लिए कोई पत्र नहीं है, और वह रिट याचिका संख्या-3541 वर्ष 1993 में इस न्यायालय के 11.08.1993 के



आदेश के अनुसार अपनी सेवाएं जारी रख रहे हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि, आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार, अपीलकर्ता को समय-समय पर अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद वेतन वृद्धि और अन्य सभी लाभ दिए गए थे। उपरोक्त तथ्यों का विवरण देने के बाद, पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता का आवेदन उचित था और उस पर अनुकूल रूप से विचार किया जाना चाहिए, और तदनुसार, प्रधानाचार्य ने अपीलकर्ता के नियमितीकरण के लिए अनुमोदन मांगा था।

7. चूंकि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, और कोई अन्य प्रभावी उपाय नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता को रिट ए संख्या-19783 वर्ष 2024 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें प्रतिपक्षियों को निर्धारित समय के भीतर 01.08.2023 को अपना प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 14.02.2025 के अपने आदेश के माध्यम से, उपरोक्त रिट याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से अधिकतम आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार अपीलकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, यह देखा गया कि इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया गया था, और प्रतिपक्षी लागू नियमों और मामले के तथ्यों के आलोक में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र थे।

8. उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, आसफपुर, बदायूं ने अपीलकर्ता की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए दिनांक 04.11.2025 का आदेश पारित किया। बंद करने के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने रिट ए संख्या-18316 वर्ष 2025 में फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 10.02.2026 का आक्षेपित आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जिसने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि यह न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमेबाजी के अंतिम दौर में इस न्यायालय द्वारा पहले पारित दिनांक 02.04.2012 के आदेश का स्थान नहीं ले सकता है। एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने



नियमितीकरण की मांग करते हुए जानबूझकर दिनांक 02.04.2012 के आदेश को छिपाया और दिनांक 14.02.2025 का अहानिकर आदेश प्राप्त किया, जिसने पहले के आदेश का खुलासा किए बिना नियमितीकरण का दावा करने वाले अपने अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।

9. अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि 33 वर्षों से अधिक समय तक अपीलकर्ता की सेवाएं लेने के बाद प्रतिपक्षियों की आक्षेपित कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और कानूनी रूप से गलत है, और इसे कानून की नजर में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, और इसलिए, एकल न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता के करियर के अंतिम चरण में 33 वर्षों से अधिक समय तक उसे संलग्न करते हुए की गई ऐसी कार्रवाई अनुचित थी और उसकी लंबी निरंतर सेवा को बंद करना, जहां उसे नियमित रूप से राज्य के खजाने से भुगतान किया जाता था, मामले के तथ्यों में मनमाना था।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने दिनांक 02.04.2012 के अपने आदेश के माध्यम से माना कि अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति अवैध थी, लेकिन प्रतिपक्षियों ने स्वयं उसे बिना किसी रुकावट के 13 वर्षों से अधिक समय तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी। चूंकि प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता भी सुनवाई के समय मौजूद थे जब उपर्युक्त रिट याचिका में बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था और उसके बाद भी प्रतिपक्षियों ने अपीलकर्ता की सेवाएं लेना जारी रखा, जबकि उसे वेतन वृद्धि और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) आदि सहित सभी लाभ देते हुए, प्रतिपक्षियों की कार्रवाई वैध उम्मीद को जन्म देती है कि अपीलकर्ता को अचानक नहीं हटाया जाएगा और उसके जीवन के एक चरण में नियमित किया जाएगा, जिससे अपीलकर्ता उसी सेवा में अपना पूरा जीवन देने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार होगा।

11. अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने आग्रह किया कि 11.08.1993 का अंतरिम आदेश, जिसमें अपीलकर्ता की सेवाओं को जारी रखने का प्रावधान किया गया था और जिसके कारण वह उस स्तर पर वापस शामिल हो गया था, यह बहुत स्पष्ट था कि प्रतिपक्षी उस पद के खिलाफ नियमित नियुक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिस पर अपीलकर्ता को सेवाएं प्रदान करना जारी रखा गया था, और यह तथ्य की बात है कि



प्रतिपक्षियों ने अंतरिम आदेश में स्वतंत्रता की पूरी जानकारी रखते हुए, उस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं करने का विकल्प चुना था और अपीलकर्ता को उस पद पर लगातार सेवा प्रदान करने की अनुमति दी थी। 1993 से 2012 तक या उसके बाद भी उस पद पर कोई नियुक्ति करने के लिए प्रतिपक्षियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था। जबकि अपीलकर्ता को उचित भुगतान और अन्य सभी लाभ देने के बाद उसकी सेवाएं ली जाती रहीं, जिसके लिए वह हकदार था। जीवन भर सेवाएं प्रदान करने और वैध बकाया प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु के किनारे पर प्रतिपक्षियों द्वारा छोड़े जाने के बजाय नियमितीकरण की वैध अपेक्षा थी, जिसका उद्देश्य उद्देश्य केवल सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में उसे वृद्धावस्था सुरक्षा से वंचित करना था।

12. अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इतनी लंबी और निर्बाध सेवा के बाद, अपीलकर्ता को जून 2026 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करनी है और इस स्तर पर उसे हटाना अत्यधिक कठोर होगा, और सेवा कानून न्यायशास्त्र के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता वृद्धावस्था संरक्षण का हकदार था और नियमितीकरण नियम 1979 के अनुसार बहुत पहले सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए पात्र हो गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.04.2012 के आदेश में अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति को भी अवैध माना गया है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है क्योंकि अपीलकर्ता को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकता है यदि वह आने वाले सभी दिनों में सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियमितीकरण योजना या नियमों के तहत पात्र था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने 02.04.2012 के आदेश की गलत व्याख्या करके यह निष्कर्ष निकाला है कि आदेश अपीलकर्ता को भविष्य में किसी भी नीति या नियमों में विचार करने की पात्रता से भी बाहर करता है।

13. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत सिफारिश पत्र में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि, नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत, 2021 के संशोधन से 31.12.2001 तक संशोधित कट-ऑफ तिथि से पहले नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में केवल तीन साल की निर्बाध निरंतर सेवा की आवश्यकता थी। यह आग्रह किया गया था कि, चूंकि अपीलकर्ता की सेवा प्रतिपक्षियों द्वारा तीन दशकों से अधिक समय तक लगातार प्राप्त की जा रही थी, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से उक्त नियमों के तहत पात्रता



मानदंडों को पूरा किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02.04.2012 के आदेश को आने वाले समय के लिए नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत अपीलकर्ता की पात्रता के निर्णायक निर्धारण के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब अपीलकर्ता संशोधित नियमों के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करता है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि दो रिट याचिकाओं में नियमितीकरण की मांग करने के तथ्य, परिस्थितियां और आधार भौतिक रूप से भिन्न थे, विशेष रूप से 2021 में नियमितीकरण नियम, 1979 में पेश किए गए संशोधन के मद्देनजर, जिसने कट-ऑफ तिथि को बदल दिया है, इसलिए, आक्षेपित निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है।

14. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन में दिनांक 02.04.2012 के आदेश का संदर्भ न दिए जाने को भौतिक तथ्यों के दमन के रूप में नहीं माना जा सकता है, खासकर जब उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित नहीं किया गया था, और यह लगभग एक दशक पुराना आदेश है, और यह अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर भी प्रदान किया गया था, न कि 2021 में संशोधित नियमितीकरण नियम, 1979 के ढांचे के तहत, जो नियमितीकरण के लिए मानदंडों के एक पूरी तरह से अलग सेट पर काम करते हैं और प्रारंभिक नियुक्ति के लिए एक अलग तारीख थी।

15. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दमन का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है और दिमाग के अनुप्रयोग को दर्शाता है, और इस प्रकार इसे कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि अपीलकर्ता की ओर से किसी भी जानबूझकर छिपाने या धोखाधड़ी का सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है। तत्स्य विपरीत, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने 33 वर्षों से अधिक की निरंतर और निर्बाध सेवा प्रदान की थी, जो 1979 के नियमों के तहत न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक थी। यह भी आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ता ने पूरे समय एक बेदाग और संतोषजनक सेवा अभिलेखों बनाए रखा है, और लागू नियमों के तहत अपनी स्पष्ट पात्रता के बावजूद, सेवानिवृत्ति के कगार पर नियमितीकरण से इनकार करना मनमाना और अन्यायपूर्ण है।

16. अंत में, अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने **श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम, गाजियाबाद, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 221, धर्म सिंह और अन्य**



उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1735, भोला नाथ बनाम झारखंड राज्य 129। झारखंड राज्य और अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 129 में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश ने और कानून दोनों पर गलती की है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है। तदनुसार यह प्रार्थना की गई थी कि प्रतिपक्षियों को अपीलकर्ता की सेवाओं को तुरंत नियमित करने का निर्देश जारी किया जाए, ताकि वह अपने सेवानिवृत्ति लाभों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके, विशेष रूप से 33 वर्षों से अधिक की उसकी संतोषजनक, निरंतर और निर्बाध सेवा के आलोक में, जिसके दौरान उसे राज्य के खजाने से भुगतान किया गया था।

17. दूसरी ओर, राज्य प्रतिपक्षियों की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता भौतिक तथ्यों को छिपाने का दोषी है, क्योंकि वह इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2012 के आदेश के माध्यम से अपनी पिछली रिट याचिका को खारिज करने का खुलासा करने में विफल रहा। आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने रिट ए संख्या-19783 वर्ष 2024 में दिनांक 14.02.2025 का आदेश प्राप्त करते समय इस तथ्य को इस न्यायालय के संज्ञान में लाने से भी चूक गई, जिसके तहत उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया था। यह भी आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ता की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में पहले ही निर्णायक निर्णय लिया गया था, और उक्त आदेश का खुलासा करने में उनकी विफलता, इसके बाद सेवा में उनकी निरंतरता के साथ, उन्हें नियमितीकरण सहित किसी भी और राहत का दावा करने के लिए अयोग्य बना देती है।

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, विचार के मुद्दे यह हैं कि क्या अपीलकर्ता की वेतन, वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के साथ तीन दशकों से अधिक समय तक निर्बाध सेवा, 2021 में संशोधित नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत नियमितीकरण की वैध अपेक्षा को जन्म देती है, और क्या उसकी लंबी और संतोषजनक सेवा की परिणति पर इस तरह के नियमितीकरण से इनकार करना मनमाना है और



स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है, जिन्हें एकल न्यायाधीश द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।

19. हमने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और अभिलेखों पर सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। एक अंतर-न्यायालय अपील होने के नाते, इस स्तर पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे की जांच करना आवश्यक है। इस पहलू पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोमा सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, (2018) 17 एस.सी.सी. 106 में सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है, जिसके बाद चंद्र प्रकाश सिंह बनाम स्कूल और अन्य जिला निरीक्षक, (2022) 155 एलआर 116 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया था:

"5. वर्तमान विशेष अपील इस न्यायालय की एकल पीठ से इस न्यायालय की एक खंडपीठ को एक अंतर-न्यायालय अपील है और एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अपील प्रदान करने का उद्देश्य खंड पीठ द्वारा स्क्रीनिंग का एक और स्तर प्रदान करना है और इसका मतलब यह नहीं होगा कि एकल न्यायाधीश खंड पीठ के अधीनस्थ है, हालांकि अपीलीय न्यायालय के आदेशों से जुड़े मिसाल और अंतिमता के सिद्धांत के कानून के तहत एकल न्यायाधीश, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से बाध्य है। अंतर-न्यायालय अपील पर निर्णय लेते समय एक खंडपीठ की शक्तियों पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोमा सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में माना है कि रिट कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली इंटरकोर्ट अपील के मामले में, खंड पीठ को मामले को एकल न्यायाधीश को भेजने के बजाय एकल न्यायाधीश के निर्णय की शुद्धता का निर्णय लेकर गुण-दोष के आधार पर अपील पर विचार करने की आवश्यकता है।

20. उपरोक्त के आलोक में, हम अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप के दायरे को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोजन के लिए, पहले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर विचार करना प्रासंगिक है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता को शुरू में 1992 में तीन महीने की अवधि के लिए



अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, और बाद में 'मैकेनिक' के रूप में उनकी नियुक्ति को 21.04.1993 तक बढ़ा दिया गया था।

21. अपीलकर्ता की सगाई को 21.04.1993 से आगे नहीं बढ़ाया गया था, जिससे उसे अपनी सेवा बंद करने के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी, जबकि प्रतिपक्षियों को पद का विज्ञापन करने और नियमित नियुक्तियां करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अंतरिम आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा, हालांकि, प्रतिपक्षियों ने नियमित भर्ती के माध्यम से पद को भरने की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने अपीलकर्ता को पद के खिलाफ स्थायी नियुक्ति करने का विकल्प होने के बावजूद, दशकों तक विस्तारित अवधि के लिए तदर्थ क्षमता में बनाए रखने का विकल्प चुना। हमारे सुविचारित विचार में, प्रतिपक्षियों द्वारा ऐसा आचरण लागू नियमों के तहत सेवा की निरंतरता और नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के अधिकार का आकलन करने में एक प्रासंगिक कारक है।

22. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता को उस पद के लिए उचित वेतन और अन्य सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए गए थे, जिसमें सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) में योगदान भी शामिल था, जिस पर उसने अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। इसके अलावा, उन्हें एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस (ए.सी.पी.) योजना के साथ-साथ 6वें आयोग के लाभ भी दिए गए थे। ये तथ्य दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता की सेवा को प्रतिपक्षियों द्वारा उसके पूरे कार्यकाल में स्वीकार किया गया और पूरी तरह से मुआवजा दिया गया।

23. यह भी निर्विवाद है कि 02.04.2012 को अपीलकर्ता की पिछली रिट याचिका को अंतिम रूप से खारिज करने के बाद भी, प्रतिपक्षियों ने एक दशक से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखा। दिनांक 02.04.2012 का आदेश एकपक्षीय पारित नहीं किया गया था, और आदेश के समय प्रतिपक्षियों का विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि अपनी प्रारंभिक नियुक्ति में अवैधता की घोषणा के बाद अपीलकर्ता की निरंतर भागीदारी प्रतिपक्षियों द्वारा सचेत रूप से विचार किए बिना थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. यह भी तथ्य की बात है कि सेवा करियर के किसी भी चरण में या इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश में, अपीलकर्ता पर कोई आरोप नहीं है कि उसने धोखाधड़ी या किसी अनुचित तरीके से नौकरी हासिल की है। इस बिंदु पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **जग्गो बनाम भारत संघ और अन्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3826** के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"10. अग्रिम प्रस्तुतियों और अभिलेखों पर सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं की लंबी और निर्बाध सेवा, दस साल से अधिक की अवधि के लिए, केवल उनकी प्रारंभिक नियुक्तियों को अंशकालिक या संविदात्मक के रूप में लेबल करके खारिज नहीं किया जा सकता है। उनके रोजगार के सार को उनके निरंतर योगदान, उनके काम की अभिन्न प्रकृति और इस तथ्य के प्रकाश में माना जाना चाहिए कि कोई सबूत नहीं बताता है कि उनका प्रवेश किसी अवैध या गुप्त मार्ग से हुआ था...

22. अस्थायी रोजगार अनुबंधों का व्यापक दुरुपयोग, जैसा कि इस मामले में उदाहरण दिया गया है, एक व्यापक प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाता है जो श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। निजी क्षेत्र में, गिग अर्थव्यवस्था के उदय से अनिश्चित रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है, जो अक्सर लाभ, नौकरी की सुरक्षा और उचित व्यवहार की कमी की विशेषता है। श्रमिकों के शोषण और श्रम मानकों को कमजोर करने के लिए ऐसी प्रथाओं की आलोचना की गई है। निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सौंपे गए सरकारी संस्थान इस तरह के शोषणकारी रोजगार प्रथाओं से बचने के लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी वहन करते हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अस्थायी अनुबंधों के दुरुपयोग में संलग्न होती हैं, तो यह न केवल गिग अर्थव्यवस्था में देखे गए हानिकारक रुझानों को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करती है जो सरकारी कार्यों में जनता के विश्वास को नष्ट कर सकती है।

25. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी कर्मचारी ने लंबी, निर्बाध सेवा प्रदान की है और राज्य के खजाने द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया गया है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह जिस भी नियम में नियमितीकरण का दावा करने में उचित है, भले ही उसकी मूल नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया हो, यह उसे यह दावा करने से नहीं रोकता है कि वह भविष्य में किसी भी नियम के तहत पात्र है। प्रतिपक्षियों द्वारा लंबे समय से चली आ रही सगाई अपीलकर्ता की ओर से उसकी सेवा के नियमितीकरण के लिए एक वैध अपेक्षा को जन्म देती है। प्रस्तुत मामले में, एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष ने 02.04.2012 के आदेश को आने वाले सभी समय के लिए नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता के दावे के खिलाफ एक निर्णायक बार के रूप में मानने में गलती की। प्रासंगिक नियम, अर्थात् नियमितीकरण नियम, 1979 के लिए केवल तीन साल की निरंतर निर्बाध सेवा, अपेक्षित योग्यता की आवश्यकता होती है, और यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति 31.12.2001 को या उससे पहले की गई थी।

26. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जबकि इस न्यायालय ने 2012 में वर्ष 1992 में अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति की जांच की और इसे अवैध घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद अपीलकर्ता की निर्बाध सेवा विवाद से परे है। सेवा की ऐसी निरंतरता उसे नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4(1) के तहत परिकल्पित लाभों का हकदार बनाती है। नियम 4(1) को आसान संदर्भ के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"4. तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण- [(1) कोई भी व्यक्ति जो- (i) 31 दिसंबर, 2001 को या उससे पहले तदर्थ आधार पर सीधे तौर पर नियुक्त किया गया था और उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर के पदों पर)(चौथा संशोधन) नियम, 2021;

(ii) ऐसी तदर्थ नियुक्ति के समय नियमित नियुक्तियों के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं रखीं; तथा

(iii) तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद या यथास्थिति, प्रासंगिक नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति में किसी भी नियमित नियुक्ति से पहले उसके अभिलेखों और उपयुक्तता के आधार पर, जो उपलब्ध हो, स्थायी या अस्थायी रिक्ति में नियमित नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।



27. उपर्युक्त नियम का नियम 8, यह स्पष्ट करता है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, जो उपयुक्त नहीं पाई जाती है या जिसका मामला नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा आच्छादित नहीं किया जाता है, की सेवा तत्काल निर्धारित की जाएगी और इस तरह की समाप्ति पर, वह एक महीने का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। प्रावधान से पता चलता है कि राज्य ने कर्मचारियों के कल्याण और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और केवल उन लोगों की सेवा समाप्त करने के लिए प्रावधान किए हैं जो नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4(1) के तहत आच्छादित नहीं हैं और इसलिए, रिट अदालत ने समाप्ति आदेश में हस्तक्षेप किया होगा, जिसे रिट ए - 19783 वर्ष 2024 में आक्षेपित किया गया था।

28. नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 9 और 10 में उन सभी व्यक्तियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है जिन्हें 01.05.1983 और 01.10.1986 को या उससे पहले तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त किया गया था, और जो उस क्षमता में सेवा में बने हुए हैं। ये प्रावधान एक मॉडल नियोक्ता के रूप में, उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य के इरादे को दर्शाते हैं, जिन्होंने निरंतर सेवा प्रदान की है, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया गया है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने रोजगार के अंतिम चरण में अपने वैध लाभों को न खोएं। इस प्रकार, इन नियमों का उद्देश्य निरंतर सेवा में तदर्थ नियुक्तियों की अधिकतम संख्या-को आच्छादित करना और उनके नियमितीकरण की सुविधा प्रदान करना है, उन मामलों को छोड़कर जहां नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4 (1) के तहत निर्दिष्ट शर्तें संतुष्ट नहीं हैं। नियम 4(1) पात्रता के लिए केवल तीन शर्तें निर्धारित करता है, पहला, कि प्रारंभिक नियुक्ति 31.12.2001 को या उससे पहले की गई होनी चाहिए, दूसरा, कर्मचारी के पास योग्यता होनी चाहिए, और तीसरा, यह कि कर्मचारी के पास न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए निरंतर सेवा होनी चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता को नियमितीकरण से इनकार, स्पष्ट और पर्याप्त सबूत के बावजूद कि वह नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4(1) के तहत निर्धारित सभी तीन शर्तों को पूरा करता है, को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।



29. हमारा विचार है कि अपीलकर्ता का दावा नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत निर्धारित शर्तों के भीतर आता है, भले ही 1992 में उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की स्थिति कुछ भी हो। तथ्यों को छिपाने के संबंध में विवाद अस्थिर है, खासकर जब से दिनांक 02.04.2012 का आदेश एकपक्षीय रूप से पारित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उस रिट में अंतरिम आदेश ने स्पष्ट रूप से प्रतिपक्षियों को अपीलकर्ता द्वारा धारित पद के खिलाफ नियमित नियुक्ति करने की स्वतंत्रता दी, हालांकि, प्रतिपक्षियों ने उस विकल्प का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया और अपीलकर्ता का लाभ उठाना जारी रखा।

30. इसके अलावा, एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि दिनांक 02.04.2012 का आदेश, अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए, नियमितीकरण के लिए उसके दावे पर किसी भी विचार को रोकता है, गलत है क्योंकि नियुक्ति प्राप्त करने में अपीलकर्ता द्वारा किसी भी धोखाधड़ी का कोई अवलोकन या आरोप नहीं लगाया गया था। यह स्पष्ट है कि दिनांक 02.04.2012 का आदेश वर्ष 1992 में अपीलकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति के बारे में था और वर्तमान दावा नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत नियमितीकरण के लिए है, जिसके लिए केवल तीन साल की निरंतर सेवा और 31.12.2001 से पहले प्रारंभिक नियुक्ति की आवश्यकता होती है। दशकों से अपीलकर्ता की निर्बाध सेवा स्पष्ट रूप से इन शर्तों को पूरा करती है, और इसलिए, उक्त आदेश नियमों के तहत उसके अधिकार पर रोक के रूप में काम नहीं कर सकता है।

31. राज्य, एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते, एक कर्मचारी को नियमितीकरण से इनकार करने के लिए प्रारंभिक नियुक्ति की सख्त तकनीकीताओं पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने तीन दशकों से अधिक समय तक लंबी और निर्बाध सेवा प्रदान की है, खासकर जब नियम प्रदान नहीं करते हैं कि न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रदान की गई निरंतर सेवा, एक कर्मचारी को नियमितीकरण के लाभों का दावा करने से अयोग्य घोषित करती है।

32. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.02.2025 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता की सेवा को समाप्त करना बिल्कुल अनुचित और मनमाना था, खासकर यदि समाप्ति आदेश अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई दशकों की निर्बाध सेवा के बाद अर्जित वैध अपेक्षा को



नजरअंदाज करने के बाद प्रतिपक्षियों द्वारा लिए गए इस तरह के निर्णय के लिए कोई उचित कारण दर्ज नहीं करता है, जिसके लिए वे उसे सभी लाभ और वेतन प्रदान कर रहे हैं। यह इस तथ्य के आलोक में अधिक अस्वीकार्य और अनुचित है कि यह निर्णय प्रतिपक्षियों द्वारा अपीलकर्ता के करियर के अंतिम चरण में लिया गया था, उनकी निरंतर निरंतर सेवाओं के 33 वर्षों के बाद लिया गया था।

33. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते उचित प्रशासनिक नियमों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। एक मॉडल नियोक्ता से निष्पक्षता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह से व्यवहार करने की जिम्मेदारियां भी वहन करता है, जो उचित है और इसलिए, प्रतिपक्षियों को उनकी वैध अपेक्षा की अनदेखी करते हुए तीन दशकों से अधिक समय तक कर्मचारियों की कम उम्र का लाभ उठाने और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु के पास बिना किसी उचित और बोलने वाले आदेश के अपनी सेवाओं को बंद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक मॉडल नियोक्ता के रूप में राज्य पर डाला गया संवैधानिक जनादेश किसी भी अन्य नियोक्ता की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है और इसलिए, एकल न्यायाधीश के समक्ष आक्षेपित आदेश वर्ष 1992 में प्रारंभिक नियुक्ति के प्रश्न की तुलना में रिट क्षेत्राधिकार में अधिक ध्यान देने योग्य है।

34. सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि लंबी और निर्बाध सेवा किसी भी कर्मचारी की सेवा के नियमितीकरण के लिए एक वैध अपेक्षा को जन्म देती है। भोला नाथ (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

"13. संविदात्मक कर्मचारियों के मामले में विचार की आवश्यकता वाला एक और पहलू, जैसे कि प्रस्तुत अपीलकर्ता, वैध अपेक्षा का सिद्धांत है। जहां कर्मचारियों ने काफी समय तक संविदात्मक पदों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा है, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, यह स्वाभाविक है कि एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होती है कि राज्य, किसी स्तर पर, उनकी लंबी और निरंतर सेवा को मान्यता देगा। यह इस विश्वास में है, कार्यकारी द्वारा दिए गए बार-बार विस्तार से बल मिलता है, कि ऐसे कर्मचारी सेवा में बने रहते हैं और वैकल्पिक



रोजगार की तलाश करने से बचते हैं, भले ही उनकी सगाई की संविदात्मक प्रकृति हो..."

35. भोला नाथ (उपरोक्त) में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि लगभग दस साल की निरंतर सेवा के बाद उस मामले में अपीलकर्ता की सेवा को बंद करने के राज्य के निर्णय के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है और उसके बाद देखा गया कि राज्य ने उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जबकि अपीलकर्ता उस मामले में सार्वजनिक सेवा में बने रहे। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि नवीनीकरण की लंबे समय से चली आ रही प्रथा से हटकर, विशेष रूप से एक जो कर्मचारी की वैध अपेक्षा को निराश करता है, बोलने वाले आदेश द्वारा दर्ज किए गए कारणों से समर्थित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि:

"13.5. ऐसा निर्णय आवश्यक रूप से एक सचेत और तर्कपूर्ण होना चाहिए। एक कर्मचारी जिसने कई वर्षों में अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन किया है और उसे बार-बार विस्तार दिया गया है, उसे रातोंरात अधिशेष या अवांछनीय नहीं माना जा सकता है। हम उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए औचित्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि राज्य का दायित्व, एक मॉडल नियोक्ता के रूप में, अपने कर्मचारियों के उचित उपचार तक फैला हुआ है, भले ही उनकी सगाई संविदात्मक हो या नियमित।

13.6. इस न्यायालय ने, कई अवसरों पर, "अंशकालिक", "संविदात्मक" या "अस्थायी" के नाममात्र लेबल के तहत कर्मचारियों को शामिल करने के राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रथा को हमेशा के लिए खारिज कर दिया है और इस तरह उनके पदों को नियमित नहीं करके उनका शोषण किया है। जग्गो बनाम भारत संघ में, इस न्यायालय ने रेखांकित किया कि सरकार-विभागों को निष्पक्ष और स्थिर रोजगार सुनिश्चित करने में उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए, और यह जांचने की परीक्षा विकसित की कि क्या ऐसे अस्थायी कर्मचारियों द्वारा किए गए कर्तव्य संगठन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के अभिन्न अंग हैं।

36. भोलानाथ (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमितीकरण के दावों पर रोक लगाने के लिए संविदात्मक शर्तें संवैधानिक गारंटी को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ओवरराइड नहीं कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि राज्य, एक मॉडल नियोक्ता के रूप में, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी, (2006) 4 एस.सी.सी. 1 के संविदात्मक स्तर या यांत्रिक अनुप्रयोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, तदर्थ कर्मचारियों को लंबे समय तक बढ़ाने या निष्पक्षता, गरिमा या संवैधानिक शासन के साथ असंगत तरीके से लंबे समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को त्यागने के लिए।

37. आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बनाम सुनील कुमार शर्मा, (2024) 16 एस.सी.सी. 598 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध अपेक्षा के सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों ने इस प्रकार अवधारित किया है:

"63. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से वैध अपेक्षा के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:

63.1. सबसे पहले, वैध अपेक्षा केवल आशा, इच्छा या प्रत्याशा के विपरीत एक अधिकार पर आधारित होनी चाहिए;

63.2. दूसरे, वैध अपेक्षा या तो एक व्यक्ति या निहित वादे से उत्पन्न होनी चाहिए; या एक सुसंगत अतीत अभ्यास या रिवाज जो अपने व्यवहार में एक प्राधिकरण द्वारा अनुसरण किया जाता है;

63.3. तीसरा, अपेक्षा जो छिटपुट या आकस्मिक या यादृच्छिक कृत्यों पर आधारित है, या जो अनुचित, अतार्किक या अमान्य है, उसे वैध अपेक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता है;

63.4. चौथा, वैध अपेक्षा मूल और प्रक्रियात्मक दोनों मामलों के संबंध में संचालित होती है;

63.5. पांचवां, वैध अपेक्षा सार्वजनिक कानून के दायरे में संचालित होती है, अर्थात्, वैध कार्रवाई की दलील केवल तभी ली जा सकती है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण किसी वादे का उल्लंघन करता है या बिना किसी उचित आधार के लगातार पिछले अभ्यास से विचलित हो जाता है।

63.6. छठा, पिछले अभ्यास के आधार पर वैध अपेक्षा की दलील केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जा सकती है जिसके पास सार्वजनिक प्राधिकरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ व्यवहार या बातचीत है। यह प्राधिकरण के लिए कुल अजनबी द्वारा केवल इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह सामान्य रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य करे।

64. उपरोक्त विशेषताएं, हालांकि प्रकृति में संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन मामले के तथ्यों के लिए वैध अपेक्षा के सिद्धांत की प्रयोज्यता को तय करने में हमारी मदद करने के लिए पर्याप्त हैं। यह स्पष्ट है कि वैध अपेक्षा, न्यायशास्त्रीय रूप से, राज्य की कार्रवाई में मनमानी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया गया एक उपकरण था। यह निजी पक्षगण के बीच अनुबंधों के संचालन का विस्तार नहीं करता है और न ही नियंत्रित कर सकता है, जिसमें वचन पत्र का सिद्धांत क्षेत्र रखता है।

38. उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों से सेवाओं का लाभ उठाने के बाद नियमितीकरण से बचने में राज्य के कार्यों के प्रति लगातार अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। इस स्थिति की आगे श्रीपाल और अन्य (उपरोक्त) में पुष्टि की गई है, जहां यह माना गया था कि:

"14. प्रतिपक्षी नियोक्ता यह तर्क देने के लिए उमादेवी (उपरोक्त) पर भरोसा करता है कि दैनिक वेतन या अस्थायी कर्मचारी इस तरह के अवशोषण प्रदान करने वाले वैधानिक नियमों के अभाव में स्थायी अवशोषण का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि, जैसा कि अक्सर दोहराया जाता है, उमा देवी स्वयं उन नियुक्तियों के बीच अंतर करती हैं जो "अवैध" हैं और जो "अनियमित" हैं, बाद वाले कुछ शर्तों को पूरा करने पर नियमितीकरण के लिए पात्र हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उमा देवी नियोक्ता द्वारा वैध भर्ती किए बिना वर्षों से बनी रहने वाली शोषणकारी गतिविधियों को सही ठहराने के लिए एक ढाल के रूप में काम नहीं कर सकती हैं। अभिलेखों को देखते हुए जो कोई वास्तविक ठेकेदार-आधारित व्यवस्था नहीं दिखाता है और स्थायी बागवानी कर्मचारियों की लगातार आवश्यकता को दर्शाता है, नई भर्ती पर कथित रूप से प्रतिबंध, हालांकि वास्तविक है, अनिश्चितकालीन दैनिक मजदूरी की स्थिति या निरंतर अनुचित प्रथाओं को उचित नहीं ठहरा सकता है।



15. यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता श्रमिकों ने कई वर्षों में लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कीं, कभी-कभी एक दशक से अधिक समय तक। यहां तक कि अगर कुछ मस्टर रोल पूरी तरह से तैयार नहीं किए गए थे, तो ऐसा करने के निर्देशों के बावजूद ऐसे अभिलेखों प्रस्तुत करने में नियोक्ता की विफलता - अच्छी तरह से स्थापित श्रम न्यायशास्त्र के तहत एक प्रतिकूल अनुमान की अनुमति देती है। भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में स्थायी दैनिक मजदूरी या संविदात्मक व्यस्तताओं का दृढ़ता से विरोध करता है जहां काम प्रकृति में स्थायी है। नैतिक और कानूनी रूप से, जो श्रमिक साल दर साल चल रही नगरपालिका आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर डिस्पेंसेबल के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से एक वास्तविक ठेकेदार समझौते के अभाव में..."

39. उपरोक्त स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, धर्म सिंह और अन्य (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"11. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं पर मुकदमा न करने के लिए उमादेवी (उपरोक्त) पर रखी गई निर्भरता गलत है। उमादेवी (उपरोक्त) के विपरीत, हमारे सामने चुनौती सार्वजनिक रोजगार की संवैधानिक योजना को दरकिनार करने का निमंत्रण नहीं है। यह नियोक्ता की आवश्यकता की अपनी स्वीकृति और कार्यबल पर दशकों की निरंतर निर्भरता के बावजूद पदों को मंजूरी देने से राज्य के मनमाने इनकार के लिए एक चुनौती है। दूसरी ओर, उमादेवी (उपरोक्त) अवैध नियुक्तियों और अनियमित व्यस्तताओं के बीच अंतर करती है और अनिश्चित रोजगार को बनाए रखने का समर्थन नहीं करती है जहां काम स्वयं स्थायी है और राज्य वर्षों से अपने घर को व्यवस्थित करने में विफल रहा है। इस न्यायालय के हालिया निर्णय जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल बनाम नगर निगम, गाजियाबाद में जोरदार चेतावनी दी है कि उमादेवी (उपरोक्त) को दीर्घकालिक "तदर्थवाद", प्रॉक्सी के रूप में आउटसोर्सिंग के उपयोग, या बुनियादी समानता से इनकार करने के माध्यम से शोषण को उचित ठहराने



के लिए ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता है, जहां समान कर्तव्यों को विस्तारित अवधि में लागू किया जाता है..."

40. यहां तक कि संविदात्मक शर्तों के लिए जहां कर्मचारी अनुबंध में सहमत हो सकता है, उच्चतम न्यायालय ने नियमितीकरण के बिना निरंतर सगाई का समर्थन नहीं किया है और लाभ प्रदान किया है, जबकि मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता दशकों से निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा था और नियमित कर्मचारियों की तरह सभी लाभों के साथ उचित वेतन प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसे नियमित नहीं किया गया है, इसके बजाय मनमाने ढंग से हटा दिया गया है, और इसलिए मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता के अधिकारों को लागू करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

41. तथ्यों के पूर्वगामी विश्लेषण, पक्षगण की प्रस्तुतियों और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को देखते हुए, हमारा विचार है कि एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत हैं, इसलिए, आक्षेपित आदेश को तदनुसार **रद्द/अपास्त** किया जाता है। अपीलकर्ता, पूर्ण वेतन, भत्ते, वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के साथ तीन दशकों से अधिक समय तक लंबी, निरंतर और निर्बाध सेवा प्रदान करने के बाद, एक वैध अपेक्षा रखता है और नियमितीकरण नियम, 1979 के नियम 4(1) के तहत निर्धारित शर्तों को स्पष्ट रूप से पूरा करता है।

42. तदनुसार, विशेष अपील की **अनुमति** दी जाती है। प्रतिपक्षियों को नियमितीकरण नियम, 1979 के तहत अपीलकर्ता की सेवाओं को कानून के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिपक्षी इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर इस निर्देश को लागू करेंगे। लागत के बारे में कोई और आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी)

मैं सहमत हूँ।

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

मार्च 31, 2026 / विक्रम